श्री यद्मपाल सिंह: माननीय मंत्री जी से मेरा यह प्रथन है कि क्या फायदा इससे ? करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद्र फिर प्राप बाद में कहेंगे कि एक्सपेरिमेंट नाकामयाब हुआ। मैं यह बताना चाहता हूं कि ऐग्रीकल्चर में जो पैदवार की कमी है वह विज्ञान की कमी के करण नहीं बल्कि पानी की कमी के कारण है। तो बजाय इसके कि विज्ञान मन्दिरों में रुपया खराब करें उस रुपये को नहरों में और ट्यूबवेल्स में लगायें। जो विज्ञान ग्राप दे रहे हैं वह बेकार है। उससे कोई फायदा नहीं हो सकता है। तो क्या ग्राप इस पर विचार करेंगे कि विज्ञान के बजाय प्रैक्टिकल नालेज होनी चाहिए?

Shri M. C. Chagla: Science is not completely useless. I assure my hon, friends that if we had more science in our country, we would have more production, better production. Our people would become scientific-minded and we shall shed some of our prejudices and superstitions and become a modern nation.

Mr. Speaker: Next Question. Mr. Vishwa Nath Pandey.

Shri Shashi Ranjan: Why does he not contradict what Mr. D. C. Sharma said about cobwebs?

Mr. Speaker: Next Question.

तेल की खोज के लिये ग्रमरीकी सहयोग

*362. श्री विश्वनाथ पाण्डेय: क्या पेट्रोलियम श्रीर रसायन मंत्री 23 मार्च, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 730 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि 1

- (क) क्या पांच अमरीकी तेल कम्पनियों ने भारत में तेल की खोज के लिये सरकार को सहयोग देने की पेशकश की है;
- (ख) यदि हो, तो क्या इस सम्बन्ध में बातचीत ग्रन्तिम चरण में पहुंच गई है; क्योर

(ग) उसका परिणाम क्या निकला है ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Iqbal Singh): (a) Interest in possible collaboration had been expressed by more than half a dozen American firms, but detailed offers have been received only from two firms.

- (b) Negotiations are in progress.
- (c) Does not arise.

श्री विश्वनाथ पाण्डेय: मैं यह जानना चाहता हूं कि इन ग्रमरीकन कम्पनियों के ग्रलावा ग्रौर भी किसी ग्रन्य-देश की कम्पनी ने इस कार्य में सहयोग देने के लिये ग्रापके पास प्रस्ताव भेजा है ?

श्री इकबाल सिंह : ये 6 ग्रमरीकन कम्पनियां हैं, जिन्होंने ग्राफर भेजी हैं—

- ऐशलैण्ड रिफायनरी कम्पनी,
- 2. कान्टीनेन्टल ग्रायल कम्पनी, . . .

एक माननीय सवस्य : सुनाई नहीं पड़ रहा है।

श्राच्यक्ष महोदय : मिनिस्टर साहब बजाये मेम्बर की तरफ़ मुंह करके जवाब दें, मेरी तरफ़ मुंह कर के जवाब दें।

श्री इकवाल सिंह : हमारे पास 6 श्रमरीकन कम्पनियों ने श्राफर भेजी थी। इन के पहले बी० श्रो० सी० ने भी कुछ इन्टरेस्ट शो किया था, लेकिन बाद में उन्होंने कह दिया कि हमें कीई इन्टरेस्ट नहीं है। इन के श्रलावा रिशया की तरफ से भी एक श्राफर शाई है, जिस में उन्होंने कहा है कि वह भी इस में कुछ इन्टरेस्ट ले सकते हैं।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय: सरकार के पास जो साधन हैं जैसे सर्वेक्षण विभाग है, उस सर्वेक्षण विभाग की ग्रोर से खोज क्यों नहीं की जाती? क्या इस का कारण

373**o**

यह है कि इस सर्वेक्षण विभाग के पास उचित और सामयिक यन्त्र नहीं हैं, जिस के कारण ये लोग इस काम को कर नहीं पाते हैं और विदेशों से सहायता लेने की भावश्यकता पड़ रही हैं?

श्री इकबास सिह: जहां तक समुद्र से तेल खोज करने का सवाल है, पिछले 10 सालों में काफ़ी तरक्की हुई है और डेक्लपमेंट हुआ है। लेकिन बहुत कम देश हैं जिनके पास समुद्र से खोज करने के साधन मौजूद हैं। इस के खोज करने के तीन किस्म के प्लेटफार्म होते हैं एक फिक्स्ड प्लेटफार्म का तरीका जो कि रिश्वयन तरीका है, दूसरा फलोटिंग प्लेटफार्म का तरीका है, जिसे अमरीका ने परफिक्ट किया है और तीसरा मोबाइल प्लेटफार्म का तरीका है, जिसे इटली और कान्टी-नेन्टल फान्स ने परफेक्ट किया है। इन मुक्कों के सिवा दुनिया में बहुत से मुक्क हैं जिनके पास थे साधन मौजूद नहीं हैं।

Shrimati Renu Chakravartty: Is it a fact that we have signed an agreement with a small American Company, namely the Ashland Oil Co. for oil exploration along the offshore coast of the Gulf of Cambay and if so, why is it that this small company has been chosen and negotiations have almost been completed within six months? May I know also whether it is correct that if they find oil, they will exploit it also?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan): It is a small company, and I think that it is an advantage because we are not combining with any of the international majors as they are called. I am surprised that the hon Member should take exception to our combining or joining with a small company. Negotiations have been going on for more than a year. It is because they have the know-how and they have the

foreign exchange which will be needed in very large quantities that we want to combine with them.

Shrimati Renu Chakravartty: My question has not been answered. It may be that I could not take my point clear. Whether it is a small company or a big company is not the point. What is it that we have found to be of special importance for us from our point of view which has made us enter into an agreement with this small company? Have we of any special advantage out of this?

Shri Alagesan: We have not enterd into any agreement with them yet. Negotiations are still going on. The agreement is still to be entered into. I have just answered what it is that has made us go to them. We do not have the technical skill and the technical know-how in the matter of offshore drilling. It is a very special kind of job and we do not have the technical know-how in that regard.

श्री भागवत का श्राजाद: एक समय था जब ग्रमरीका के एक बड़े ग्रमरीकी श्री डलेस ने कहा था कि हिन्दुस्तान की भूमि में एक बून्द भी तेल नहीं मिल सकता है। लेकिन ग्राज ये ग्रमरीकन कम्पनियां बड़े जोश से हिन्दुस्तान में ग्राना चाहती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि खाद की तरह से ऐसी कौनसी रियायतें भारत सरकार ने उनको दी हैं, जिससे उन्होंने बिलकुल राइट एवाउट टर्न कर लिया है ग्रीर यहां ग्राना चाहती हैं।

धो इकवाल सिंह: इस बात का कोई सवाल नहीं है। जहां तक हिन्दुस्तान में ममरीकन कम्पनियों के ग्राने का ताल्लुक है, कुछ ग्रमरीकन कम्पनियां पहले भी हिन्दुस्तान में बीं ग्रीर वे ग्रपनी रिफायन-रीज यहां पर लगा रही हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूणन सिस्टम बहुत पहले का यहां पर है। जहां तक हिन्दुस्तान की ग्रपनी खोज का ताल्लुक हैं, हिन्दुस्तान ने इस में काफी

तरक की है। बहुत से देशों ने इस
में हमारो मदद भी की है, रूस ने भी मदद
को है और देशों ने भी की है। अब
दे क्यों भाना चाहती हैं, इसलिये
भाना चाहती हैं कि हिन्दुस्तान चाहता
है कि अपने समृद्र से क.फ. सारा तेल
निकाले ताकि हमारी कूड आयल की
कमी पूरो हो सके। अब जो उन काम
को कर सकता है, उसको ही वह काम
दिया जा सकता है।

श्री रामे उचरान द: हम जब भी सरकार की बात सुनते हैं, भाषण सुनते हैं, तो उसमें यही सुनाई देता है कि हिन्दुस्तान ने बहुत तरको को है. परन्तु जब भी कोई छोटे ते छोटा काम हो, या बड़े से बड़ा काम हो, यो हर जाह यही कहते हैं कि हमारे यहां ऐसे विशेषज्ञ नहीं हैं, हम को इतना ज्ञान नहीं हैं हम को इतना ज्ञान नहीं हैं कि हम उस काम को कर सकें श्रीर बाहर से विशेषज्ञों को बुलाते हैं, ऐसी स्थित में साप कैसे श्रास्म-निर्मर हो सकेंगे। श्राप तेल को हो लीजिये या किसी भी चीज को सीजिये, श्राप कैसे श्रास्म-निर्मर होंगे श्रीर हो सकेंगे तो कब तक ?

श्री इक बाल तिहः आत्म-निर्मर होने के लिये कोशिश हो रही है और जरूर आत्म-निर्मर होंगे, एक दिन ऐसा जरूर आयेगा जब हम आत्म-निर्मर हो जायेंगे।

श्री जिन्नतारायणः जापान पड़ौसी मुल्क है, श्रीर यह मुल्क सऊदी श्ररेबिया में तेल निकालने में बड़ा एक्सपर्ट माना जाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने जापान के किसी श्रादमी को यहां भाने का मौका दिया है?

श्री इक बाल सिंह: हमने मौका नहीं दिया है। लेकिन जागान वाले अगर इसमें किसी किस्म का इन्टरेस्ट शो करेंगे तो हम उसको खश मामदीद कहेंगे।

Shri P. C. Borooah: Have Government fixed any basic criteria relating to the maximum profit that can be repatriated in foreign exchange and also equity participation in regard to this foreign collaboration? If so, what are they?

Shri Alagesan: The hon, Member was not present here. Government will hold 51 per cent of the shares and the foreign collaborator 49 per cent.

I should like to put this question in proper perspective. During the Third Plan period, we had to import as much as 32 million tons of crude cil costing in foreign exchange Rs. 318 crores; in the Fourth Plan period, it we has been estimated that have to import about 49 million tons of crude oil costing .470 crores foreign exchange. If by additional effort, we are able to find even one million tons of crude oil, it will mean a saving of about Rs. 9:5 crores in foreign exchange. That urgency.

Shri Nambiar: Arising out of the first questions, the Hon. Minister answered that the Soviet Union is not in a position to drill oil off-shore beyond 50 feet, whereas to the second question the reply was that the Soviet Union has offered to collaborate. In regard to the reply to the second question, why is it that the Soviet Union is not taken as a collaborator for drilling oil because the Soviet Union is very much interested in getting oil for India?

Shri Iqbal Singh: I have only said that the Soviet method is practical only to drilling upto 50—60 feet depth. The Soviet Union have also mentioned this and said that they are ready to do drilling upto 50—60 feet. Our difficulty is that the structures we have so far delinated are more than 50—60 feet deep. They go to 200 feet deep.

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh: The Minister spoke about Russian inclination to collaborate in this field. May I know what were the Russian suggestions about the development of indigenous capacity in terms of suitable

drills and platforms and allied machinery for offshore drilling, and to what extent the Russians were prepared to enter into financial collaboration on rupee payment basis?

Shri Iqbal Singh: As I said earlier, there are three ways of drilling offplatform shore. One is the fixed method or the Russian method; this can be practical only upto 50-60 feet. The second is the floating platform method; this is a method the Americans have specialised in. It can drill 600 feet. The third is the mobile method which can go from 50 to 200 feet.

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh: The question which has been put must be answered, to what extent the Russians were prepared to finance it.

Mr. Speaker: If that method was not suitable, where is the question of Financing it?

Shri Daii: In view of our own and Pakistan's sad experience that these American and English companies went on drilling but failed to produce any oil, has/any time limit been placed for possible drilling operations, or has any limit been placed on the marketing of the produce if the produce is manufactured?

Shri Alagesan: As far as marketing goes, we will take the entire oil that is to be found, because of our deficit. Our imports of crude oil are very large at present.

Shri Daji: Who will market it in India the Government or the company?

Shri Alagesan: It will be sold to us. We will own 51 per cent of it; we will take the other 59 per cent at a fixed price.

Shri Nambiar: What about the time-limit?

Shri Alagesan: The time limit will be 20 years.

Mr. Speaker: He wanted to know whether there is a time limit for the possibility of exploration, for finding out whether actually the oil is there or not, not the whole term of lease that will be entered into.

Shri Alagesan: If we start exploration now, it may take about three years for us to know whether there is oil or not. We will be able to produce oil only after three years.

Workers in Rayon Factories

*365. Shri S. M. Banerjee: Will the Minister of Labour, Employment and Rehabilitation be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that the people working in Rayon Factories generally suffer from the occupational diseases due to fume:
- (b) if so, the steps taken to compel the employers to get all the workers insured at their cost; and
- (c) the nature of other amenities to be provided for workers in these factories?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shrl Shahnawas Khan): (a) Workers working in Viscose Rayon Factories are likely to suffer effects of vapour of Carbon disulphide, sulpher dioxide and hydrogen sulphide if proper hygienic measures are not adopted.

- (b) The question of compelling employers to insure their workers at their cost does not arise as factories are covered under the Employees State Insurance Act, 1948 and the workers are provided medical treatment, sickness and disability benefits under the Act.
- (c) The provision of amenities governed by the Factories Act, 1948 and the State Inspectors of Factories are empowered to see that these are provided.

Shri S. M. Banerjee: The answer is most unfortunate. My question was whether it is a fact that the people